भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2522
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

समग्र शिक्षा योजना को जारी रखना

2522. **श्री हरीश चंद्र मीना:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समग्र शिक्षा योजना को 31 मार्च, 2026 के बाद भी जारी रखने और 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल के लिए कार्यान्वयन की संशोधित अवधि, परिव्यय और केन्द्रीय हिस्से को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है और यह जारी किए गए और उपयोग किए गए केन्द्रीय हिस्से का कितना प्रतिशत है;
(ग) 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में टोंक और सवाई माधोपुर सहित कितने पीएम श्री विद्यालयों का चयन किया गया है और कितने विद्यालय चल रहे हैं; और
(घ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए सर्वेक्षण में स्कूल न जाने वाले कितने बच्चों की पहचान की गई है तथा टोंक और सवाई माधोपुर का लिंग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए अनुमोदित समग्र शिक्षा योजना 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो गई। तथापि, वित्त मंत्रालय ने योजना को 1 अप्रैल, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक जारी रखने के लिए अंतरिम विस्तारित किया है। समग्र शिक्षा योजना के वर्ष 2026-27 की अवधि का बजटीय अनुमान 42,100/- करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2026 के बाद योजना जारी रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाना है।

(ख): समग्र शिक्षा योजना के तहत, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपनी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के अनुसार वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं। इन वार्षिक योजनाओं का मूल्यांकन योजना के कार्यात्मक और वित्तीय मानदंडों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

तदनुसार, वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए राजस्थान राज्य को 3,705.07 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से को मंजूरी दी गई और 2,982.26 करोड़ रुपये (80.49%) जारी किए गए। इस विभाग के प्रबंध पोर्टल पर राज्य द्वारा 4,486.87 करोड़ रुपये के व्यय (राज्य हिस्सेदारी सहित) की सूचना दी गई है।

(ग): पीएम श्री योजना के तहत, राजस्थान राज्य से 100 केंद्रीय सरकारी स्कूलों (64 केंद्रीय विद्यालय, 35 नवोदय विद्यालय और 1 एनसीईआरटी) सहित कुल 749 स्कूलों का चयन किया गया है और वे पीएम श्री स्कूलों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनमें से टोंक जिले के 3 केंद्रीय सरकारी स्कूलों (2 केंद्रीय विद्यालय और 1 नवोदय विद्यालय) सहित 19 स्कूलों और सवाई माधोपुर के 3 केंद्रीय सरकारी स्कूलों (2 केंद्रीय विद्यालय और 1 नवोदय विद्यालय) सहित 13 स्कूलों का चयन किया गया है और वे पीएम श्री योजना के तहत कार्य कर रहे हैं।

(घ): विभाग के प्रबंध पोर्टल (2024-25) पर राज्य द्वारा अपलोड/प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 10311 बच्चों (5297 छात्र, 5012 छात्राएं और 2 ट्रांसजेंडर बच्चे) को स्कूल से बाहर के बच्चों (ओओएससी) के रूप में निर्धारित किया गया है। इनमें से, टोंक और सवाई माधोपुर जिले में राज्य द्वारा क्रमशः 85 बच्चों (43 लड़के और 42 लड़कियां) और 281 बच्चों (158 लड़के और 123 लड़कियां) को ओओएससी के रूप में निर्धारित किया गया है।

*****